

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29042023-245542
SG-DL-E-29042023-245542असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 49
No. 148]	DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 49

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सं. फा. 1/10/2022-न्याय/अधी.विधि./879.885.-अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 12 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री अमन प्रताप सिंह को उनके द्वारा कार्यभार सम्भालने की तिथि से, स्थायी पद पर, योग्यता के क्रम में अस्थायी रूप से दो वर्षों की परिवीक्षा पर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त करते हैं:-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यार्थी के चरित्र तथा संबंधित प्राधिकारियों से अभ्यार्थी के पूर्ववृत्तों का सत्यापन तथा जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, के अनुसार होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग श्रेणी, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।
- उपर्युक्त नियुक्ति अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी।

- 4 दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के पद का वेतनमान 7वां सीपीसी संशोधित कॉरस्पॉन्डिंग पे मैट्रिक्स और पे लेवल के मैट्रिक्स 13ए के स्तर में 131100-216600 रुपये + सामान्य भत्ते जैसा समय-समय पर इस संबंध में लागू हो के अनुसार है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 28th April, 2023

F.No. 1/10/2022-Judl./Suptlaw/879-885.—In pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Mr. Aman Pratap Singh, as member of the Delhi Higher Judicial Service against permanent post in temporary capacity in order of merit on a probation period of two years w.e.f. the date he assume the charge of his office.

2. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the candidate from the concerned authorities and verification of his caste certificate/PH category certificate, if applicable. If the verification reveals that the claim to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Higher Judicial Service from time to time.
4. The post carries the scale of pay of members of the Delhi Higher Judicial Service Rs.131100 – 216600 in level 13A of matrix of 7th CPC Revised Corresponding Pay matrix and Pay Level plus allowances as admissible under the Rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.